



HOW US PROFITS FROM THE WAR IN UKRAINE

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

The advocates of the US military industrial complex are deeply embedded in the government and semi-government apparatus, manipulate politicians in Capitol Hill

COACHES MATTER IN SPORTS

How Apples Got Their Names

ये “हाईकमान” क्या चीज़ है?

कांग्रेसाध्यक्ष खड़गे ने इसका मतलब समझाते हुए कहा, सोनिया गांधी 21 साल कांग्रेसाध्यक्ष रहीं, राहुल गांधी भी पूर्व कांग्रेसाध्यक्ष हैं, अतः दोनों मिलकर संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं, अतः वे हाईकमान कहलाते हैं

-रेण मित्तल-
नई दिल्ली, 30 जून। जब 140 साल पुराने एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोर देकर कहते हैं कि “हाईकमान तय करेगा”, तो न केवल आश्वास होता है, बल्कि कुछ बुनियादी सवाल भी खड़े हो जाते हैं - खासकर उस अध्यक्ष के स्टेटस या उसकी कमी को लेकर, और इस बारे में भी, कि पार्टी में वास्तव में हाईकमान और निर्णय लेने वाली समिति की संरचना क्या है।

यहाँ बात की जा रही है मलिकार्जुन खड़गे की, जो दस की सबसे राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष है - एक ऐसी पार्टी, जिसने संतुत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारत को ब्रिटिश शासन के शिकंजे से मुक्त कराया।

खड़गे अपने गुरु राज्य कनटिक्ट में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं पर बुल्ले गए - सबल का जबाब देते थे, जो हाईपार्टी के दो घड़े आपस में सत्ता की जग में उलझे हुए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धार्हेन्द्र पद पर बने रहना चाहते हैं, बढ़कि उनके प्रतिद्वंदी और उपमुख्यमंत्री डी.के.

- मजे की बात है, कि मलिकार्जुन खड़गे ने अपने आप को “हाईकमान” में शामिल नहीं किया।
- पर, एक नाम जो जुङाना चाहिए था, और शायद शिष्टाचार के कारण हाईकमान की परिभाषा में नहीं जुङा, वह था, के.सी. वेंगुपोपाल।
- राहुल गांधी को पार्टी के निर्णयों की बारीकी में जाने की आदत नहीं है, अतः उनके निजी सचिव वेंगुपोपाल, पार्टी के छोटे-बड़े निर्णय अपने स्तर पर लेते हैं। कांग्रेसाध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रस्तावित नाम को अस्वीकार करने का अधिकार वेंगुपोपाल के पास है।
- यह कांग्रेस “हाईकमान कल्चर” अब कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है, भाजपा अन्य पार्टियों ने भी यह कल्चर अपना लिया है। लीडर नेतृत्व प्रदान करता है, पर, लीडर तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, जी. हुजूरी।

शिवकुमार इस प्रतिष्ठित पद की ओर देख रहे हैं शुरूआत की संभावनाओं पर बुल्ले गए - सबल का जबाब और अन्य दलों ने कोंग्रेस से ही ली है - जो कार्यकाल का सम्भव हुआ था, और नेता की चाहकाता और जी-हुजूरी में भी “हाई कमान” आपने देख दिया है। कांग्रेसाध्यक्ष कामयम रहता है, तो यह बदलाव नवंबर कामयम रहता है, तो सबल यह है कि यह हाईकमान आपने रहना चाहते हैं, बढ़कि उनके अधिकार को लिया जाए।

हाईकमान की संस्कृति भाजपा और अन्य दलों ने अपने आपस में ही ली है - जो कार्यकाल का सम्भव हुआ था, और नेता की चाहकाता और जी-हुजूरी में भी पार्टी के संचारों वैज्ञानिक पर्याप्ति के लिए चाहते हैं। लेकिन यह एक ही रास्ता है, जी. हुजूरी।

लेकिन यह केवल शब्दों की बाजारीरी थी, सिर्फ हवा में डाला गया था। जब कोई और उनके इस्तेमाल के लिए कहा जाता है, अदालत ने कहा कि हाईकमान के पास इस संबंध में जो भी एडवाइजरी आई थी, उसे संविधित को भेज दिया गया है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस

‘मैं भी डिजिटल ठगी का शिकार होते-होते बचा’

जयपुर, 30 जून। राजस्थान हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट व साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों में बढ़ावीरी से जुड़े मामले में केंद्र व राज्य सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के पास इस संबंध में जो भी एडवाइजरी आई थी, उसे संविधित को भेज दिया गया है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम. श्रीवास्तव ने डिजिटल और सायबर क्राइम पर चिंता जाता है यह बात कही और केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस भेजा।

मनीष शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश डिजिटल अरेस्ट व साइबर क्राइम के अपराध के मुद्रे पर लिए गए स्प्रेट्रिट प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान, सीजे श्रीवास्तव ने जालीव श्रीवास्तव की चाहिए और उनकी जिम्मेदारी लेने वाली होकर कि डिजिटल ठग उन तक पी पहुंचे हैं और उनका कद अध्यक्ष के आगे बहुत छोटा

मोदी ने दलील दी थी कि उन्हें जब बीसीसीआई का उत्तराध्यक्ष नियुक्त किया गया था और साथ ही वे अधीपीएल गवर्नरी कार्यसिल के अध्यक्ष भी थे (जो बीसीसीआई की एक उप-समिति है), तो अपनी याचिका में यह माना की थी कि बीसीसीआई के नियम-कानूनों के अनुसार, बीसीसीआई को उनकी जिम्मेदारी लेने वाली होकर कि उनका चुकाना चाहिए।

बीसीसीआई का उत्तराध्यक्ष नियुक्त किया गया था और साथ ही वे अधीपीएल गवर्नरी के अनुसार, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को राजीव शर्मा को रिलीफ करने के लिए चिन्हित लिया है।

सुनवाई के दौरान, जीवंत श्रीवास्तव ने राजीव कुमार शर्मा को राजस्थान का डीजीपी नियुक्त किया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट से ललित मोदी को झटका, अब उन्हें ई.डी. को देने होंगे 10.65 करोड़ रु.

यह जुर्माना उन पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत लगाया गया था

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 30 जून। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेट प्रशासक ललित मोदी को उस याचिका के खिलाफ एक अप्रैल के अधिनियम के तहत लगाया गया था। नियमों उन्हें आपने एक अप्रैल के दो घोषणाएं देने की मांग की थी कि वह फैरन एक्सेंज मैनेजमेंट एक्स्ट्रेट (एपी.ई.एम.ए) के उल्लंघन के लिए, प्रतिवेदन दिलाया गया था। नियमों उन पर लगाया गया था।

- ललित मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि ई.डी. ने उन पर 10.65 करोड़ रु. का जुर्माना लगाया है, वह बी.सी.सी.आई. अदा करे।
- गत वर्ष दिसंबर में बांधे हाईकोर्ट ने भी उनकी यह याचिका खारिज कर दी थी उल्लेख उन पर एसी याचिका दायर करने के लिए एक लाख रु. का जुर्माना भी लगाया था।

रेमेडीज़ का सहायता होती है। बर्बाद हाई कोर्ट ने भी पिछले साल 19 दिसंबर को मोदी की इसी याचिका को खारिज कर दिया है, उन पर 1 लाख रुपये की जुर्माना लगाया था। मोदी ने अपनी याचिका में यह माना की थी कि बीसीसीआई के प्रत्यक्ष विवरणों की जुर्माना लगाया था। नियमों उन पर लगाया गया था।

मोदी ने दलील दी थी कि उन्हें जब बीसीसीआई का उत्तराध्यक्ष नियुक्त किया गया था और साथ ही वे अधीपीएल गवर्नरी कार्यसिल के अध्यक्ष भी थे (जो बीसीसीआई की एक उप-समिति है), तो अपनी याचिका में यह माना की थी कि बीसीसीआई को प्रत्यक्ष विवरणों की जुर्माना लगाया गया था। नियमों उनकी जिम्मेदारी लेने वाली होकर कि उनका चुकाना चाहिए।

मोदी ने दलील दी थी कि उन्हें जब बीसीसीआई की इसी याचिका को खारिज कर दिया गया था और उनकी जिम्मेदारी लेने वाली होकर कि उनका चुकाना चाहिए। अपनी याचिका को खारिज कर दिया गया था और उनकी जिम्मेदारी लेने वाली होकर कि उनका चुकाना चाहिए।

1976 में 42वें संसदेशन अधिनियम के तहत “समाजवादी”, “धर्मनियोक्ता” और “अखंडता” द्वारा संविधान की चाही विवरणों की जुर्माना लगाया गया था, जो इंदिरा गांधी संविधान द्वारा प्रस्तावित की गयी थी। इस अधिनियम के तहत यह याचिका लगाया गया था। नियमों उनकी जिम्मेदारी लेने वाली होकर कि उनका चुकाना चाहिए।

संसदेशन प्रस्तावित नियमों में यह याचिका लगाया गया था, जो इंदिरा गांधी संविधान द्वारा प्रस्तावित की गयी थी। इस अधिनियम के तहत यह याचिका लगाया गया था। नियमों उनकी जिम्मेदारी लेने वाली होकर कि उनका चुकाना चाहिए। इस अधिनियम के तहत यह याचिका लगाया गया था। नियमों उनकी जिम्मेदारी लेने वाली होकर कि उनका चुकाना चाहिए।

इसी याचिका के तहत यह याचिका लगाया गया था। नियमों उनकी जिम्मेदारी लेने वाली होकर कि उनका चुकाना चाहिए।

भाजपा से इस्टीफ़े के लिए उनकी जिम्मेदारी लेने वाली होकर कि उनका चुकाना चाहिए।

भाजपा से इस्टीफ़े पर दो घोषणाएं होती हैं। इनमें से दोनों घोषणाएं उनकी जिम्मेदारी लेने वाली होकर कि उनका चुकाना चाह

विचार बिन्दु

क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। -प्रेमचंद

बिहार में बवाल, चुनाव आयोग पर सवाल

रत के चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को दिशा निर्देश जारी कर बिहार की मतदाता संघीयों के विशेष सभन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का कार्य 25 जून से प्रारंभ करने की निर्णय लिया है। यह पूरे देश में भी समय समय पर लागू होगा। इस संबंध में मुख्य निवाचन आयोग द्वारा बिहार के मुख्य निवाचन अधिकारी को पत्र लिया गया है। मुख्य निवाचन आयोग ने इस एक ऐतिहासिक पत्र बताया है।

निवाचन आयोग ने अपने निर्देशों में लिया है कि उनके द्वारा यह कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32.6 एवं लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 16 के अंतर्गत दिए प्रावधानों को लागू करने के लिए किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह बताया गया है कि सभी वैध मतदाताओं के नाम समाप्ति सूची में हो एवं अवैध और अयोग्य मतदाताओं के नाम सूची से हटाया जा सके। आयोग ने सभन विशेष पुनरीक्षण के लिए तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण, लोगों का एक स्थान से दूरी स्थान पर रोजगार की तलाश में अधिक जाने, 18 साल की आयु प्राप्त करने एवं कई की मृत्यु होने तथा इन्हें अवैध रूप से भारत में निवाच कर रहे लोगों के नाम मतदाता सूची में होने को आधार बताया है।

सामान्यतया, प्रतिवर्ष मतदाता सूचीयों का पुनरीक्षण किया जाता है एवं किसी भी विधानसभा/लोकसभा चुनाव के पूर्व संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाता है। सामान्य पुनरीक्षण और विशेष सभन पुनरीक्षण में अंतर यही है कि सामान्य पुनरीक्षण, मतदाता सूचीयों को केवल संशोधित करने के लिए किया जाता है जबकि विशेष सभन पुनरीक्षण के माध्यम से सारी मतदाता सूचीयों नई बनाई जाती है।

निवाचन आयोग के निर्देशानुसार संविधान भी बोलाओं के द्वारा सभी मतदाताओं को घर घर एक गणना प्रत्र वितरित किया जा रहा है। इसे मतदाता भर कर जी एल ओ को देना होगा। यह गणना प्रपत्र निवाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा और जो भी मतदाता चाहे, उसे डाउलोड कर पाएं। इसको भवर के स्वयं भी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। निवाचन आयोग ने अपेक्षा की है कि सभी राजनीतिक दलों की एल ओ एवं अंतर्गत बृह लेवल एजेंट, इस कार्य में सहयोग करें। साहायक निवाचन अधिकारी द्वारा 25 जूलाई, 2025 तक प्राप्त प्रपत्रों के अधार पर एक ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अगस्त, 2025 को किया जाएगा। इस पर आधिकारी 1 सितंबर तक प्राप्त की जाएंगी जिनका निस्तारण 26 सितंबर तक करने के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर, 2025 को होगा। ड्राफ्ट सूची पर किसी मतदाता को आधिकारी नहीं तो वह पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट के वहाँ और दूसरी अपील मुख्य निवाचन अधिकारी कर चाहए।

हालांकि चुनाव नुकसान विशेष सभन पुनरीक्षण के कार्य को संविधान और जम्म प्रतिनिधित्व कानून की भावनाओं को लागू करने वाला बताया है किंतु इन निर्देशों के जारी होते ही पूरे विवर में बवाल मचा दूखा है। सभी विपक्षी दल इस कदम को निवाचन आयोग द्वारा भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने के रूप में किया जाता है। यह नियमित प्रक्रिया है जिसके बारे में किसी को बहुत नहीं हुआ।

भारत के चुनाव में हर वह व्यक्ति मतदाता करने का अधिकारी है जो भारत का नागरिक हो, जिसे आयोग नहीं घोषित किया गया हो और जिसकी आयु मतदाता के साल में 1 जनवरी को 18 वर्ष या उससे अधिक हो। चुनाव से पूर्व 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम जोड़े जाते हैं, किंतु इन निर्देशों के लिए एक विवरित क्रिया या "summary revision" और कभी क्रिया के रूप में किया जाता है। यह नियमित प्रक्रिया है जिसके बारे में किसी को कभी आपात नहीं हुआ।

पिछला विशेष सभन पुनरीक्षण का कार्य 2003 के चुनाव के समय हुआ था। 22 वर्ष बाद अचानक इस निर्णय का अंतिम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। इसी कारण हमारा भाजपा हुआ है और चुनाव आयोग पर आपोने लगा रहा है कि वह इसके माध्यम से लाखों लोगों के नाम मतदाता सूचीयों से हटाना चाहता है। यह आशंका वार्षिक रूप से उत्तम प्रभाव के रूप में किया जाता है।

साधारणतया, सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भर कर लेने पड़ता है और इसके आधार पर नाम अकित हो जाता है, किंतु इसके माध्यम से उत्तम प्रभाव के रूप में किया जाता है। इसके प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह तो भविष्य ही बताएगा कि बिहार के लाखों लोग किस प्रकार से अपनी नागरिकता के लिए दस्तावेज़ जुटा पाएं और प्रस्तुत कर पाएं?

यदि बहुत बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाता केवल नागरिकता के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाने के कारण सूची में अकित नहीं करवा सकते हैं।

जिन मतदातों के नाम 2003 के बाद जोड़े गए हैं तन नामकों को अपनी नागरिकता के साथ ही एक विवरित लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए किसी विवरित क्रिया को करने के बाद जोड़े गए हैं तन नामकों को अपनी नागरिकता को अपनी नागरिकता के साथ ही एक विवरित लोगों की समझ में नहीं आ रहा है।

जब नागरिकता संघोंधन कानून बनाया गया एवं एनआरसी बनाने की बात हुई है, तब पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। उसका आधार यही थी कि देश में लाखों करोड़ों एवं व्यक्ति विवरित करने के बाद जोड़े गए हैं तन नामकों को अपनी नागरिकता को अपनी नागरिकता के साथ ही एक विवरित लोगों की समझ में नहीं आ रहा है।

यह तो भविष्य ही बताएगा कि बिहार के लाखों लोग किस प्रकार से अपनी नागरिकता के लिए दस्तावेज़ जुटा पाएं और प्रस्तुत कर पाएं?

यदि बहुत बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाता केवल नागरिकता के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाने के कारण सूची में अकित नहीं करवा सकते हैं।

जिन मतदातों के नाम 2003 के बाद जोड़े गए हैं तन नामकों को अपनी नागरिकता के साथ ही एक विवरित लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए किसी विवरित क्रिया को करने के बाद जोड़े गए हैं तन नामकों को अपनी नागरिकता को अपनी नागरिकता के साथ ही एक विवरित लोगों की समझ में नहीं आ रहा है।

जब नागरिकता संघोंधन कानून बनाया गया एवं एनआरसी बनाने की बात हुई है, तब पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। उसका आधार यही थी कि देश में लाखों करोड़ों एवं व्यक्ति विवरित करने के बाद जोड़े गए हैं तन नामकों को अपनी नागरिकता को अपनी नागरिकता के साथ ही एक विवरित लोगों की समझ में नहीं आ रहा है।

जिन विवरित क्रियाओं के नाम 2003 के बाद जोड़े गए हैं तन नामकों को अपनी नागरिकता के साथ ही एक विवरित लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए किसी विवरित क्रिया को करने के बाद जोड़े गए हैं तन नामकों को अपनी नागरिकता को अपनी नागरिकता के साथ ही एक विवरित लोगों की समझ में नहीं आ रहा है।

यह तो भविष्य ही बताएगा कि बिहार के लाखों लोग किस प्रकार से अपनी नागरिकता के लिए दस्तावेज़ जुटा पाएं और प्रस्तुत कर पाएं?

यदि बहुत बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाता केवल नागरिकता के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाने के कारण सूची में अकित नहीं करवा सकते हैं।

एक और बात उल्लेखनीय है कि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों के नाम विवरित क्रिया के लिए एक विवरित लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए किसी विवरित क्रिया को करने के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों की समझ में नहीं आ रहा है।

यह तो भविष्य ही बताएगा कि बिहार के लाखों लोग किस प्रकार से अपनी नागरिकता के लिए दस्तावेज़ जुटा पाएं और प्रस्तुत कर पाएं?

यदि बहुत बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाता केवल नागरिकता के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाने के कारण सूची में अकित नहीं करवा सकते हैं।

यह तो भविष्य ही बताएगा कि बिहार के लाखों लोग किस प्रकार से अपनी नागरिकता के लिए दस्तावेज़ जुटा पाएं और प्रस्तुत कर पाएं?

यह तो भविष्य ही बताएगा कि बिहार के लाखों लोग किस प्रकार से अपनी नागरिकता के लिए दस्तावेज़ जुटा पाएं और प्रस्तुत कर पाएं?

यह तो भविष्य ही बताएगा कि बिहार के लाखों लोग किस प्रकार से अपनी नागरिकता के लिए दस्तावेज़ जुटा पाएं और प्रस्तुत कर पाएं?

यह तो भविष्य ही बताएगा कि बिहार के लाखों लोग किस प्रकार से अपनी नागरिकता के लिए दस्तावेज़ जुटा पाएं और प्रस्तुत कर पाएं?

यह तो भविष्य ही बताएगा कि बिहार के लाखों लोग किस प्रकार से अपनी नागरिकता के लिए दस्तावेज़ जुटा पाएं और प्रस्तुत कर पाएं?

यह तो भविष्य ही बताएगा कि बिहार के लाखों लोग किस प्रकार से अपनी नागरिकता के लिए दस्तावेज़ जुटा पाएं और प्रस्तुत कर पाएं?

यह तो भविष्य ही बताएगा कि बिहार के लाखों लोग किस प्रकार से अपनी नागरिकता के लिए दस्तावेज़ जुटा पाएं और प्रस्तुत कर पाएं?

यह तो भविष्य ही बताएगा कि बिहार के लाखों लोग किस प्रकार से अपनी नागरिकता के लिए दस्तावेज़ जुटा पाएं और प्र

